इसलिए सर, मैं चाहूंगा और मेरी मांग है कि वेशेषज्ञ चिकित्सकों तथा अधिकारियों का एक दल उस क्षेत्र में भेजा जाए जो वहां जाकर यह देखे कि समस्या क्या है? अगर आवश्यकता पड़े तोसांसदों का एक दल भी वहां भेजा जाए क्योंकि करीब करीब तीन हजार बच्चों की वहां मौत हुई है और हाल ही में दो बच्चे वहां पर मरे हैं।

महोदय, यह कुपोषण का प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You please concUide. You have already taken four minutes.

SHRI VIJAY J. DARDA: Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Thank you, Mr. Darda. So kind of you. Shri John F. Fernandes.

Denial of Visa to Indian Scientists and their expulsion by U.S.A.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. My submission is regarding post-Pokhran nuclear fall-out. Internationally the impact of this fall-out is more on USA. We have seen in the last week or so that one of our scientists. Dr. Chidambaram, who wanted to pursue his academic mission in the United Nations to explain the Indian point of view on the nuclear issue *vis-a-vis* not signing the NPT and the;CTBT, was denied a US visa. That country has every sovereign right or duty to deny the visa to any person. I am not disputing that. I am on a different point. The UN Headquarters is in New York and the visa to the delegates to the UNO is given by the Government of USA. So, my request to the Government of India—our Prime Minister is likely to visit the UNO in September this year—is that we have to make a request that the UN Headquarters should be stationed either in Africa or in Asia. Among many other nations India is the only country which pays its dues to the United Nations unlike the USA, one of the so-called superpowers, one of the powers who is policing the whole world. I would request the Prime Minister to consider this issue seriously. If Dr. Chidambaram is needed by the UN mission at New York, he will not be permitted. I want this anomaly to be removed. The Government of India should take up this issue strongly that the UN Headquarters should be shifted out of USA and it should be stationed in India.

I think the Government of India and the people of India will not object to give them one Island in Andaman and Nicobar. We have hundreds of them. I hope the Government of India will take up this issue very strongly and see to it that the developing countries are not belittled and no arms are twisted to sign NPT and CTBT. Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I want to associate myself with this issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I have three more names with me on this issue. Let them first speak. Then you can associate yourself with this issue. Prof. Malhotra.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, जो फर्नाडिस साहब ने सवाल उठाया है कि चिदम्बरम् साहब को वीसा नहीं दिया गया और जब यू.एन. ओ. बनाया गया था उसमें इस तरह की कमिटमेंट दी गई थी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। परन्तु जो सवाल मैंने दिया था वह यह था कि 7 वैज्ञानिकों को जो इस समय अमरीका में काम कर रहे हैं, निकल जाने के लिए कहागया है और यह बताया गया है कि 75 दूसरे वैज्ञानिकों को निकालने के लिए नोटिस दिए जाने की बात की जा रही है। यह जो अमरीका का रवैया है, इसकी सारे सदन को निंदा करनी चाहिए। अमरीका की यह कार्यवाही न केवल पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग की है, बुली करने की है क्योंकि हमने अणु विस्फोट किया है इसलिए हमारे वैज्ञानिक जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको निकाल देना या भेज देना, यह अमरीका का बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। चीन को अमरीका ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। वह चार-चार विस्फोट अपने यहां करते जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके साथ मिल कर अभी क्लिंटन साहब ने

वहां जा कर दोनों ने मिल कर के जो बयान दिया है, वह बयान भी दुर्भाग्यपूर्ण था। पाकिस्तान के साथ भी उनका रवैया बिलकुल दूसरी तरह का है। अमरीका यह जो कार्यवाही कर रहा है 7 वैज्ञानिकों को निकालने की तथा 75 वैज्ञानिकों को निकाने के नोटिस दिये जाने की और चिदम्बरम साहब को वीसा नहीं दिया गया, मैं यह चाहता हूं कि सारा सदन मिल कर इसकी निंदा करे।

श्री राम दास अग्रवाल (राजस्थान): मैं एसोसिएट करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I am confident that on this issue the whole House will associate itself. So there is no problem. Shri K.R. Malkani.

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): Sir, some of our most leading scientists have been refused visas. Many more scientists have now been asked to leave America. This can only hurt America. In the case of sanctions also they discovered that it will probably hurt them more than us. Actually, it can be said that we are giving them more scientific and technological assistance than they are giving us. Most of our IIT graduates go to America and help their industry and science and technology. Our technology Parks are also helping them. Not only that, the Y-2K problem and the bug about the millennium in computers, are being solved by the Indian engineers here and also in America. When President Clinton congratulated" Shri Atal Bihari Vajpayee on becoming P ime Minister, he pointed out that they have thousands of Indian engineers there who were doing excellent work in Silicon Valley. Shri Vajpayee told him, "you need them there and we also need a lot of them here". Sir, although the US establishment is behaving in this funny manner, the heart of people of America is sound. The American Physical Society, which has a membership of 41,000 has condemned the action of the Clinton Government in refusing visas to Indian scientists. However, the Government at its level has to respond to what the US establishment has done. It is for the Government to consider whether we should retaliate and ask some American scientists to go back or refuse visas to scientists wanting to visit India. Or, we might even consider asking the science and technology Attache in the US Embassy to go back home. They only understand the language of 'tit for tat'.

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बात कही गई है, मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं। मुखय बात यह है कि अमरीका ने हमारे सात भारतीय वैज्ञानिकों को निकाला और 75 को निकालने की बात सोच रहे हैं, यह एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय कनवेंशन का भी उल्लघंन है। वियाना कान्फ्रेंस के अनुसार मित्र देशों से जो भी नागरिक दूसरे देशों में जाते हैं, उनका इस प्रकार से प्रत्यार्पण नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार भी संभवत: नहीं आता। अनयथा ऐसा कुछ करने से पहले वे भारत से बात तो कुछ करते। उन्होंने भारत से बिना बात किए हुए एक प्रकार से प्रताड़ना करनी प्रारंभ कर दी है जो कि नितांत अनुचित है। भारत सरकार से मेरी दरख्वास्त है किसारे मामले पर वे विचार करें और अमेरिका से बात करें कि किस प्रकार से उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियम है, व्यवस्थाएं हैं, शिष्टाचार है। अगर इस प्रकार से अमेरिका अमैत्रीपूर्ण कार्य करेगा भारत के विरूद्ध तो इससे कोई बड़ा अच्छा वातावरण देश में बनने वाला नहीं है। क्लिंटन यहां आना चाहता हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ पुन: मित्रता प्रारंभ हो, एक अच्छा वातावरण बने। लेकिन एक ओर तो अमेरिका के उप-राज्य विदेश मंत्री यहां पर आए और उन्होंने एक मित्रतापूर्ण वातावरण बनाने की बात की और दूसरी ओर तत्काल इस प्रकार का जो कार्य है यह किया गया है। सदन इसकी निन्दा करता है और इससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Can we go on record that the entire House associates itself with it? Yes.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Sir, I want to say something of some significance on this issue and I concur

with the sentiments of this House. On this issue, I just want to add something of some significance. Most of the Members of this House are aware that there is a separate U.N. Organisation called the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). It has a Charter and one of the points in the Charter of UNESCO is that there must be scientific exchanges between one country and another. The action of the United States is a direct violation of the Charter of another U.N. Organisation and I want to place this fact on record. Therefore, instead of acting in a peurile and childish manner and suggesting that there should be Tit for Tat, I think that we should act in , a mature manner because we are a society with a far greater culture. We don't have any respect for those who cat in this *fashion...(Interruptions)*

श्री रामदास अग्रवालः उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था क्या वह कोई मैच्योर नहीं है ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): He is associating himself with it.

SHRI KAPIL SIBAL: Therefore, I suggest that the Prime Minister should take it up at the international level with Mr. Frederico Mayor, who is the Director General of UNESCO, and make it an international issue. That is what I want to place on record.

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान)**:** ऐसा होना चाहिए। पहले भी होता था। "सठे साठयम समचारेत" में कोई दिक्कत नहीं है।

Creation of New States

श्री जितेन्द्र प्रसाद (उत्तर प्रदेश)**:** मैं आज सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नये राज्यों के गठन की घोषणा सत्ताधारी दल ने एक बार नहीं कई बार की। जब जब चुनाव आते हैं, तब तब इस प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं और उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उन मांगों कें ऊपर उन आश्वासनों के ऊपर टालमटोल की राजनीति की जाती है।

मैं उत्तराखंड के मामले पर – उत्तरांखड कहें या उत्तरांचल कहें – कहना चाहता हूं। 8-10 साल से यह मांग उठी थी। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अंदर एक कमेटी बनी थी। हमारे इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री रमा शंकर कौशिक जी ने एक रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी थी। उसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि उत्तराखंड का राज्य बनाया जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश की असेम्बली में तीन-तीन बार सर्व-सम्मति से सभी दलों ने प्रस्ताव पारित किया कि उत्तराखंड का राज्य बनाया जाए। हमारी युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने लाल किले से भी आश्वासन दिया था कि उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाएगा। जब हमारे प्रधान मंत्री चुनावी दौरा कर रहे थे तो तलद्धानी की जनसभा में और देहरादून की जनसभा में उन्होंने जनता को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 90 दिन के अंदर हम राज्य का गठन करेंगे। आज दिन तो बीत चुके हैं लेकिन तरह-तरह के आश्वासन अब भी मिल रहे हैं और सत्ताधारी दल और उसके समर्थक दलों के बीच में जो मतभेद उत्पन्न हुए हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि जो आश्वासन दिया गया है उसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। सदन के बाहर गृह मंत्री जी ने भी कई आश्वासन दिये हैं। यहां तक कि सत्ताधारी दल के विधायक आज इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए हैं। समाचार पत्रों ने छापा है कि हमारे गढ़वाल के भारतीय जनता पार्टी के विधायक इन्हीं की पार्टी की ढलमुल नीति के कारण विधान सभा और पार्टी से अपने मेरा सिर्फ यह कहना है कि यह जो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस खिलवाड़ को रोका जाए। आप हस्तक्षेप करें। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस सदन के समक्ष आएं और कम से कम तत्काल यह बताएं कि कब यह विधेयक सदन के अंदर पेश करेंगे और कब तक यह कार्यवाही पूरी होगी? चाहे वह राष्ट्रपति जी के पास उस विधेयक को जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति फिर से शायद असेंबली में भेजेंगे और असेंबली से पिर वह विधेयक वापस आएगा। मेरा सिर्फ यह कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को कब तक पूरा करेंगे। मैं चाहता हूं कि यह सत्र स्थगित होने से पहले इस सदन के अंदर एक स्पष्ट आश्वासन गृह मंत्री जी द्वारा दिया जाए ताकि वहां की जनता जो इस वक्त भ्रमित हो रही है, जिसमें आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और जिसको सत्ताधारी दल और उसके समर्थक दल भावना फैला कर के वहां की जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक ऐसा जनपद उत्तराखंड के अंदर है जहां पर कि पी.ए.सी. तैनात करने की जरूरत पड़ रही है। इस